सभी योजनाओं का एक अप्रैल से सोशल ऑडिट

- बन रहा स्वतंत्र निदेशालय, मुख्यमंत्री की मिल चुकी है मंजूरी
- सामाजिक अंकेक्षण पर कार्यशाला में नीतीश मिश्रा ने दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, पटना : पहली अप्रैल से राज्य में चल रही सभी सरकारी योजनाओं का सोशल आडिट होगा। इसके लिए स्वतंत्र निदेशालय बन रहा है, जिसके गठन को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मंजूरी मिल चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत चलने वाली योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण पर शनिवार को आयोजित कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने यह जानकारी दी।

मिश्र ने बताया कि इस स्वतंत्र निदेशालय के लिए बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। यह केवल मनरेगा ही नहीं, बल्कि सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करेगा। यह सरकार का अंग नहीं होकर, स्वतंत्र रूप से काम करेगा। कार्यशाला का आयोजन दो फरवरी से 200 पंचायतों में शुरू होने वाले मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी के लिए आयोजित हुआ। मंत्री ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण का मकसद गलतियां पकड़ना नहीं, बल्कि कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। कार्यशाला को ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एसएम राजू, मनरेगा आयुक्त दीपक आनंद, ■ शेष पृष्ठ 17 पर

ग्रामीण विकास मंत्रालय की रक्षिता और गुरजीत सिंह, जन जागरण मंच के आशीष, एक्शन एड के विनय ओहदार सहित कई विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी।

मनरेगा आयुक्त के दावे को मंत्री ने खारिज किया : मनरेगा आयुक्त दीपक आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि सूबे में मनरेगा रास्ते से भटक गई है। यह अफसोस की बात है, लेकिन उनके बाद कार्यशाला को संबोधित करने आए ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यान्वयन में बहुत सुधार हुआ है। मनरेगा में पारदर्शिता के लिए बिहार को 02 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है। 2012 तक स्थिति भले ही बहुत खराब थी। एक संस्था के सर्वे में तो यहां तक बताया गया था कि मनरेगा की 73 प्रतिशत राशि की गलत निकासी हो जाती है।

12 डीडीसी को कारण बताओ नोटिस : ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एसएम राजू ने कहा कि कार्यशाला में उपस्थित नहीं होने वाले 12 उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें इतना गैरजिम्मेदार भी नहीं होना चाहिए।